US Secretary of Energy Ms. Hazel O' Leary in February 1995, it was agreed that the US Government would provide support in developing the alternatives to counter guarantee further based on the experience in other countries and a workshop could be organised in which US financial institutions, US Department of Energy, USAID and US project developers could participate.

(b) The prospects for investment by the US companies in the Indian power sector are bright which may be seen from the response received from US based companies (including NRIs and Joint Ventures). 23 private power proposals for a capacity addition of 12869 MW involving investment by US companies are at an active stage.

(c) No, Sir.

(d) The Government is working on alternatives to Government of India counter guarantee such as direct supply of power by Independent power Producers (IPPs) to HT consumers, opening of an escrow account for which identified payment by consumers are credited and the payment liability to the IPP is a first charge on this account, linking power generation with distribution, PPA with Power grid Corporation, World Bank guarantee and other alternatives.

विद्युत उत्पादन पर विदेशी कम्पनियों को दी जाने वाली प्रति गारंटी का प्रभाव

322. **श्री रामजेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण में अमरीकी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए फाइनैंसियल काउन्टर गारन्टी सिस्टम अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तहत अभी तक कुल कितनी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रणाली को अपनाने के कारण देश में विद्युत उत्पादन तथा परियोजना निर्माण की लागत में भारी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या यह सच है कि सरकार ने भविष्य में इस प्रणाली को न अपनाने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) निजी विद्युत नीति के प्रति सम्भावित निवेशकर्ताओं में विश्वास जागृत करने के लिए विदेशी निवेश की दृष्टि से प्रारम्भ में स्वीकृत 8 निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों के भुगतानों की राज्य विद्युत बोर्डों के लिए राज्य सरकारों की गारन्टी को भारत सरकार की प्रति गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया था । आठ परियोजनाओं में से दो के लिए प्रति-गारन्टी सम्बन्धी हस्ताक्षर पहले ही किए जा चुके हैं ।

(ग) जी, नहीं । दूसरी ओर प्रति-गारन्टी से परियोजना ऋण पर ब्याज की दर कम होने से परियोजना लागत कम होगी और इसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन की लागत कम होगी ।

(घ) चूंकि भारत सरकार की प्रति-गारन्टी को एक अस्थायी उपाय के रूप

में अपनाया गया है, इसलिये और विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की प्रति-गारन्टी न देने का निर्णय लिया गया था ।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा, भारत सरकार की प्रति-गारन्टी के सम्बन्ध में विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी एस) द्वारा उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं को सीधे ही विद्युत की आपूर्ति करना, एसक्रो खाता खोला जाना जिसमें उपभोक्ताओं की सुनिश्चित देय राशि के स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को भुगतान की प्राथमिकता का प्रावधान होता है, विद्युत उत्पादन को वितरण से, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को पावरग्रिड कारपोरेशन से जोड़ना, विश्व बैंक गारन्टी तथा अन्य विकल्प शामिल हैं ।

Losses of State Electricity Boards

323. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the cumulative losses of State Electricity Boards at the end of the Seventh Five Year Plan and the estimated loss at the end of the Eighth Five Year Plan;

(b) the factors responsible for losses of State Electricity Boards;

(c) whether the power sector is heading towards a major crisis requiring urgent attention by Government; and

(d) if so, strategy devised by Government to tackle the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) The cumulative losses of the 17 State Electricity Boards (SEBs), functioning in the country, were Rs. 3351.23 crores after taking into account RE subsidy as provided in the accounts, at the end of the 7th Five Year Plan (1989-90). The estimated losses during the first three years of the 8th Five Year Plan, as per planning Commission after taking into accounts the RE subsidy as provided in the accounts are as under:—

Year	(Rs. in crores)
1992-93 . . .	2435.18
1993-94 . .	2961.65
1994-95 . . .	3850.44

(b) The major reasons for the losses of SEBs include un-scientific power tariff structure including that for agricultural sector, non-payment of RE subsidy to SEBs by the State Governments, non-conversion of loan into equity, low level of PLF, high T&D losses, high fuel consumption in thermal power stations etc.

(c) The shortage between requirement and availability of power during 1992-93, 1993-94 and 1994-95 (upto January, 1995) was as under:—

Year	Shortage	Percentage
1992-93 . .	25442 MU	— 8.3
1993-94 . .	23758 MU	— 7.3
1994-95 . . (upto Jan. '95)	20597 MU	— 7.1

(d) The various short-term and long-term measures taken to improve the availability of power in the country are as under:—

Short-term Measures:

(a) Inter-State and Inter-Regional exchange of power.

(b) Renovation and Modernisation Programme.

(c) Implementation of Short-gestation projects.

(d) Supply of adequate quantity & quality of Coal.